भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3264
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

जवाहर नवोदय विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

†3264. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के कर्मचारी किसी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार की देश में नए जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): नई पेंशन योजना (अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) (एनपीएस), जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.01.2004 से शुरू किया गया था, को नवोदय विद्यालय समिति के नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से लागू किया गया था। नवोदय विद्यालय समिति में दिनांक 01.04.2009 से पहले नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को मौजूदा अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को जारी रखने या एनपीएस को चुनने का विकल्प दिया गया था। नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारी उनके द्वारा दिए गए विकल्प के संबंध में या तो सीपीएफ योजना या एनपीएस के लाभ के हकदार हैं।

(ग) और (घ): नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) खोलने की परिकल्पना की गई है। नवंबर 2016 में 62 नए जनवि की मंजूरी के साथ, इस योजना को स्वीकार करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी 638 जिलों को (31 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार), 100% शहरी जनसंख्या वाले 6 जिलों को छोड़कर, इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 06.12.2024 को देश के कवर न किए गए जिलों में 28 नए जनवि भी स्वीकृत किए गए हैं। नए जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराए और स्थायी भवन के निर्माण तक स्कूल चलाने के लिए किराया मुक्त, आवश्यक अस्थायी भवन, उपलब्ध कराए। नए जनवि की मंजूरी और उन्हे खोलना मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है।

*****